पैसा मार लिया जाना, पैसों को लेकर लोगों से अपशब्द सुनना और मार खाना, आवास न होने के कारण खुले आसमान के नीचे पार्क व सड़क के डिवाइडर पर रात गुजारना, राशन कार्ड न बन पाने के कारण किरासन बाजार भाव पर लेना, किसी किस्म का बीमा न होना, भार ढोने के कारण सांस व अन्य रोग हो जाने की सम्भावना और कोई पहचान न होना आदि–आदि।

इनकी इन समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास शुरू हुये। रिक्शा चालकों एवं निर्माण मजदूरों के साथ सबंध बनाये गये व उक्त मुद्दो पर चर्चा शुरू की गई। तत्पश्चात सभी कार्य क्षेत्रों के समूहों के गठन की पहल की गई। समूहो की उपयोगिता को समझकर लोग इससे जुड़ने लगे उनके अपने अधिकारों के प्रति और अधिक समझ बनाने के लिये पम्पलेट बांटे गये। विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बैठकें की गई जिनमें जिलाधिकारी, मेयरसाहब, नगरनिगम के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया। तथा स्वास्थ कैम्प भी लगाये गये इन प्रयासों से समुदाय में बीमा कराने वाले सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

शहरों में जगह की कमी लगातार हो रही है। ऐसे में इन प्रवासियों के लिये आवास जुटाना टेढ़ी खीर है। मजबूरी में उनका आसरा बनते है वो आवास जो मानव के लिये अनउपयुक्त है। यहां के हालात सुधारनें के प्रयास शुरू हुये। नगर निगम, जलसंस्थान, जलनिगम के साथ जनपैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी के दिनों में जगह–2 प्याऊ लगाये गये, नल लगे, निजी हैण्ड पम्पों की मरम्मत हुई।

जबकि लखनऊ शहर में सिर्फ 6800 मजदूर ही पंजीकृत हैं। सरकार केवल उन्ही को पहचान पत्र जारी करती है जिनका पंजीकरण हो चुका है शेष मजदूरों का भी पंजीकरण हो इसके प्रयास किये जा रहे है नगर निगम में रिक्शा चालकों के लिये किराये का निर्धारण कराने व इनके वोटर कार्ड बनवाने और श्रम कानूनों का प्रभावी कियान्वयन करवाने की दिशा में गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।

उम्मीद है सरकारी विभाग कामगार सामाजिक सुरक्षा बिल सन 2008 के लागू हो जाने के बाद असंगठित क्षेत्र से जुड़े देश के इन नागरिकों के पहचान के संकट को दूर करने के प्रयास तेज करेगी और इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिये कृतसंकल्प होगे ताकि देश में विभिन्न हिस्सों से शहरों को आये ये प्रवासी यह सोचने पर मजबूर न हो जाये कि बहुत कुछ खोया.... बहुत कम पाया....।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

Participatory Action for Community Empowerment (PACE)

Head Office: 1/22, Jankipuram Extn.,
Sitapur Road Scheme, Lucknow,
Uttar Pradesh (India)
Tel: +91 522 2771761
Email: pacelko2000@gmail.com
Website: www.pacelko.org.in

शहरी गरीबी

क्या खोया... क्या पाया...

सिटी मेकर्स प्रोग्राम

Programme Partner

Participatory Action for Community Empowerment (PACE)

Programme supported by

IGSSS, New Delhi

शहरी गरीबी

क्या खोया..... क्या पाया.....

जब गरीबी पर बात होती तो आमतौर पर हमारे सामने ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन ही होते है, यहां तक कि निर्धनता उध्नमूलन की योजनाऐं भी प्रायः गांवो को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। जबकि शहरों में गरीबी की स्थिति कम भयावह नही है। योजना आयोग के अनुसार शहरी निर्धनों की संख्या वर्तमान समय में 8 करोड़ तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के आस–पास के क्षेत्रों से लगभग 4–6 लाख लोग गांव के हालातों से तंग आ कर, मजबूर होकर रोजगार की तलाश में लोग शहरों की तरफ पलायन करते है। यह सही है कि ग्रामीण निर्धनों की तुलना में शहरी गरीबों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलते है, लेकिन ये प्रायः अनियमित और असंगठित होते हैं इसलिए आय को लेकर शहरी गरीब खुद को हमेशा असुरक्षित महसूस करते है। न तो उन्हें रहने के लिए ढ़ग का मकान मिल पाता है और न ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वचिंत रहते है। शहरों में आकर सड़क किनारे फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी पर अपनी जिन्दगी बिताने को मजबूर है। ये बेघर श्रमिक शहरी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है जो शहर और

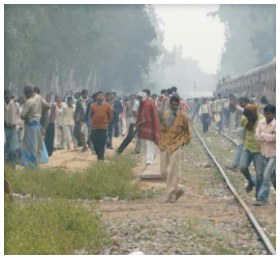

देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते है।

लखनऊ शहर में लगभग 6 लाख प्रवासी कामगार होने के आंकड़े मौजूद है जो असंगठित क्षेत्र की विभिन्न रोजगारों से जुड़े हैं। इनमे शामिल है रिक्शा चलाने वाले निर्माण मजदूर,ठेला खीचनें वाले, निर्माण मजदूर, ठेला खीचनें वाले तथा कबाड़ बीनने वाले आदि।

देश में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बिल 30दिसम्बर 2008 को लागू किया गया है। सुरक्षा बिल को लागू करने का उददेश्य देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़े लगभग 37 करोड़ 30लाख कामगारों के हितों की रक्षा करना,जबकि कामगारों का 53 प्रतिशत हिस्सा स्वःरोजगार का हिस्सा है। लेकिन असंगठित श्रम बाजार लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इसमें शामिल हो रहे हैं बेहतर आजीविका की तलाश में फैलते शहरों में आये झुंड के झुंड ग्रामीण जन जो पलायन कर रोजी रोटी की तलाश में शहरो में आते है, जाते हैं मगर एक निश्चित रोजगार,आवास जैसा आवास तथा अपनी पहचान को स्थापित कर पाने के संकट से लगातार जूझते रहते हैं।

सरकार द्वारा उनके हितों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अनभिज्ञ हैं तथा

उनका लाभ उठा पाने में असमर्थ हैं।

इनकी इन्हीं स्थितियों में सुधार लाने के लिये और इन अति गरीबों को शहरी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये लखनऊ में सिटी मेकर्स (पहले पर्ल परियोजना के रूप में जाना जाता) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र के 1500 रिक्शा चालकों व 1000 निर्माण मजदूरों व 500 घरेलू कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है तथा उनको मूलभूत सुविधायें व अधिकार को दिलाना है तथा उन्हें संगठित करके उनको पहचान दिलाना ही पेस संस्थान का लक्ष्य है।

उपरोक्त स्थितियों को देखते हुये पेस संस्थान ने सिटी मेकर्स प्रोग्राम (आई0जी0एस0 एस0एस0) के सहयोग से शहरी गरीब वर्ग के समुदाय के लोगों के बीच में कार्य करते हुये इन लोगों को जागरूक करने व इनका हक दिलाने को प्रयासरत है।

इस कार्य में पेस संस्थान द्वारा योजना का कियान्वयन लखनऊ शहर के 12 कार्यक्षेत्रों में लागू किया जा रहा है योजना के शुरूआती चरण में इन रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को पूरे महीने काम न मिलना, पूरा पैसा न मिलना, ठेकेदारों द्वारा